श्री शाहनवाज खां : हमारे सामने हैंटर्स की जरूरियात लगभग 20 हजार की है और उन में से करीब आधे हम बनाते हैं।

Shri D. C. Sharma: Evidently the prospects for this agro-industries corporation were not very bright because only two States have agreed to come forward to set up such a corporation.

Shri A. P. Sharma: More than two.

Shri D. C. Sharma: Are you the Minister? I want to know what efforts are being made in order that this agro-industrial corporation which is going to give some hope to the small agriculturist will become a going concern?

Shri Shahnawaz Khan: We have written to the States and we are taking into consideration what their difficulties are. Initially the Central assistance was to be of the order of 25 per cent. Later on, the States said that they would like that to be enhanced, and it was increased to 50 per cent. We have been emphasising the urgency of such corporations and we hope the State Governments will come forward.

Shri M. R. Krishna: Birla Brothers have started the cultivation of grapes in Andhra Pradesh on a very extensive scale, and they have been given a licence for a distillery. May I know whether distilleries are also considered as coming within agro-industries?

Shri Shahnawaz Khan: It does not come under this.

श्री बागड़ी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो ये कृषि उद्योग निगम स्थापित किए जा रहे हैं, इन के सिलसिले में जो देहाती किसान हैं उनकी जरूरत के भी उन से सुझाव मांगे गए हैं कि उनको किस किस चीज की और किस किस समय पर जरूरत होती है ?

श्री शाहनवाज खां : किसान की जो जरूरियात हैं उन का अन्दाजा लगाया गया है।

Australian Aid for Agricultural Projects

\+
*451. Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri D. C. Sharma:
Shri Bagri:
Shri D. J. Naik:
Shri Ravindra Varma:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Australian Freedom from Hunger Campaign Committee has agreed to assist India in five major agricultural projects to increase food production and improve the living standards of the farmers; and

(b) if so, the nature of the schemes so far drawn up?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) A statement giving a brief description of the 5 projects is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-4767/65].

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, इस स्टेटमेंट में आइटम नम्बर 2 को देखने से पता चलता है कि सरकार इस योजना के अन्तर्गत 750 आदमियों को प्रति वर्ष ट्रेनिंग देगी कि होटलों में खान पान का कैसा इन्तिजाम किया जाए। गांवों में जो परिवार हैं उनके यहां अगर कुछ खाना बच जाता है तो वह मवेशियों को खिला दिया जाता है। लेकिन आज शहरों में देखा जाता है कि होटलों में जो खाना बचता है वह बरबाद जाता है या सड़ जाता है। क्या सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जहां होटल्स चलाए जाएं वहां कुछ मवेशी भी रखे जाएं ताकि जो खाना बचे वह उन मवेशियों को खिला दिया जाए ?

श्री शाहनवाज खां : इन होटलों में जो खाना बच जाता है वह जाया नहीं जाता, बल्कि दिल्ली के जो बड़े बड़े होटल हैं उन में उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से कुछ मुलाजिमान को खाने के लिए दे दिया जाता है और कुछ को लोग मवेशियों के लिए ले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह भी तजवीज हो सकता है कि इन्सान और मवेशियों को साथ साथ बांध दिया जाए।

श्री विभूति मिश्र : इसी स्टेटमेंट के आइटम नम्बर 4 को देखने से पता चलता है कि इस योजना का सुझाव यंग फारमर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने दिया है और इसके अन्तर्गत फल पैदा करने का, सब्जी पैदा करने का और मुर्गी और मुर्गी की पैदावार का इन्तिजाम होगा। इसमें मुर्गी के बारे में तो एक और जगह भी लिखा है कि उनका उत्पादन होगा, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि फलों और साग सब्जी के उत्पादन के लिए क्या किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फलों और सब्जी का निरादर कर रही है?

श्री शाहनवाज खां : यह भी इसी में शामिल होगा। सौ एकड़ जमीन इसमें रखी गयी है जिसमें सब्जियां और भी पैदा किए जाएंगे और मुर्गियां भी पाली जाएंगी।

श्री का० ना० तिवारी : इस स्टेटमेंट में यह दिया गया है कि एफ ए ओ और आस्ट्रेलिया की योजना के अधीन 15 जगह सेंटर खोले जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी जगहों में ये सेंटर बनाए जा चुके हैं? दूसरी बात, इसकी ट्रेनिंग के लिए मद्रास में, आन्ध्र में और इज्जत नगर में और दूसरी जगहों पर सेंटर रखे जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हर प्रान्त में इन सेंटर्स को रखने का विचार है जिससे कि हर प्रान्त के लोग उन से फायदा उठा सकें?

श्री शाहनवाज खां : ये प्रसंग दो स्कीम हैं। पहली है वह तो मेनली पोल्ट्री के बारे में है, बाबूगढ़ में उसका एक सेंटर खोल दिया गया है। वहां पर पोल्ट्री ब्रीडिंग के साथ साथ उनकी खुराक वगैरह की मशीनें भी लगायी गयी हैं, ताकि पोल्ट्री ब्रीडर्स को सस्ते दाम पर मुर्गियों का खाना मुहय्या किया जा सके, और इरादा है कि हर एक सूबे में एक सेंटर खोला जाए, लेकिन फिल हाल बाबूगढ़ में एक खोला गया है।

दूसरा सेंटर जो रिसर्च पैन्ट वगैरह के लिए है वह इज्जतनगर में खोला जाएगा, और वहां ट्रेनिंग के लिए सब जगह से लोग आ सकते हैं।

Shri D. C. Sharma: Is the government aware of the fact that freedom-from-hunger campaign in most of the western countries of the world paints a very very drak picture of India, showing children with bulging bellies and men and women who are semi-naked? It is only by presenting such pictures that they get money for this campaign. May I know if the government will look into it and see to it that India is not painted in such black colours, while trying to get money for this campaign?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): I have seen the advertisements; it is not particularly with reference to India, but generally the conditions existing in the backward, under-developed countries are put there. No particular country is mentioned.

Shri D. C. Sharma: I have seen it myself.

Shri C. Subramaniam: After all, in some areas deplorable conditions do exist in our country and certainly we should see that these things are removed. We cannot ignore the existing conditions.

Mr. Speaker: Shri Yashpal Singh. Shri Kapur Singh.

Shri Kapur Singh: May I know whether, with a view to solve our food problems, our government have ever considered the simple idea of letting the farmer own and cultivate as he chooses, while ensuring him the necessary inputs?

Shri C. Subramaniam: That is quite a different thing; this is for the purpose of improving the technology.

Shri Kapur Singh: Have they ever considered this simple idea and if so, with what results? The idea is simple, the question is simple. Yet the answer is not there.

Mr. Speaker: The answer was rather simpler.

Shri Kapur Singh: It was rather evasive.

श्री बड़े : हिन्दुस्तान के गांवों में रिंडर-पेस्ट की बीमारी से प्रति वर्ष लाखों ढोर मर जाते हैं । क्या इसकी रिसर्च के वास्ते सरकार विद्यार्थियों को बाहर भेज रही है और उसके लिए यहां कौनसी व्यवस्था की जा रही है जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है ?

श्री शाहनवाज खां : पहला हिस्सा समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि रिंडर-पेस्ट से बहुत से जानवर मारे जाते हैं ।

श्री शाहनवाज खां : रिंडरपेस्ट की बीमारी बहुत मूजी बीमारी है जो हिन्दुस्तान के जानवरों को नुकसान पहुंचाती है । हम ने एक नेशनल प्रोग्राम फार इरेडिकेशन आफ रिंडरपेस्ट शुरू किया है और तकरीबन देश के सभी प्रान्तों में हम इसके लिए काफी काम कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किसी को इसके लिए बाहर भी भेजा है ।

श्री शाहनवाज खां : हमारे पास काफी टेक्निकल लोग हैं और किसी को इसके लिए बाहर भेजने की जरूरत नहीं है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: After reading the statement and hearing the objectives stated by the hon. minister in reply to Mr. Sharma's question, are we not correct in assuming that these five schemes are more for propaganda and demonstrative purposes for the giver and, if not, how far will these schemes have an impact upon the States and upon the masses?

Shri C. Subramaniam: It is true that it is for demonstration purposes so that others also may adopt these techniques of production, processing and all those things. These things are absolutely necessary.

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह ।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें नाम था ।

अध्यक्ष महोदय : आप रिकार्ड देख सकते हैं । मैंने आप को बुलाया था, पर आप उठे नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं माफी चाहता हूं । मुझे एक सवाल करने का मौका बाद में दे दें ।

श्री बूटा सिंह : इस भूख की समस्या को हल करने के लिए सिख गुरुद्वारों में बगैर किसी जाति, मजहब या रंग के इम्तियाज के रोज कुछ हजार लोगों को खाना दिया जाता है । गुरुद्वारों के नाम जो जमीन लगी हुई है, उसके सहारे ये लंगर चलते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसा हिदायत देगी कि इन जमीनों को लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के मातहत न लाया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत दूर तक चले गये । अब आप इनवीटेशन दे रहे हैं कि गुरुद्वारों के अन्दर की जमीन को भी इसमें ले आया जाय ।

Shri Kapur Singh: The question is on food production. So, it has a direct bearing on this.

श्री यशपाल सिंह : यह कुछ साफ़ नहीं किया है कि यह जो जमीन उन्हें दी जायगी यह कोआपरेटिव से लेकर दी जायगी या प्राईवेट ओनर से लेकर दी जायगी ? गवर्नमेंट फार्म्स जो उनमें इस्टेबलिश किये जायेंगे यह जमीन कहां से आयेगी और क्या किसानों को यह हक़ दिया गया है कि किसान अपने यहां एक्सपेरीमेंट कर सकें ?

श्री शाहनवाज खां : जो जो शक्ल जमीन की है और जिस सूरत में जमीन मिल सकती है अगर कहीं सरकारी जमीन है तो प्रान्तीय सरकार मुफ़्त में दे सकती है लेकिन अगर ऐक्वायर करनी है तो उसके लिए लैंड एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी । अलग अलग जगह पर जैसे जैसे हालात होंगे उनके मुताबिक़ जमीन दी जायगी ।

Shri R. S. Pandey: The purpose of this project is to increase the standard of living of the farmers. May I know whether Government is aware that so many things are produced by farmers, like eggs, milk, etc. and since they have a good market in the cities those things go to the cities? I want to know whether Government is thinking of providing facilities to the farmers to consume those first and then sell only what is left behind?

Shri Shahnawaz Khan: It is up to the farmer to decide what he wants to do with his production. If he thinks that by selling his poultry he can buy something which he requires more urgently, he can do so.

Shri Shree Narayan Das: May I know the extent to which the financial requirements of this project will be met by the Centre and the States?

Shri Shahnawaz Khan: Some allocation is made by the States and some money is received from the donor countries. It varies.

Shri Shree Narayan Das: It is a vague answer. What is the figure?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam): The foreign exchange position and the internal finance to be used are given in the statement.

Mr. Speaker: If it is given there then it need not be repeated.

श्री चं० लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार की बहुत सी जमीनें परती पड़ी हुई हैं जिनको कि अगर उपजाऊ बनाकर खेती उनमें की जाये तो मुल्क को उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है तो मैं चाहता हूं कि पोलिटिकल सफरसं जो कि भारत की आजादी की जंग के दौरान आप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं, झगड़े हैं और अनेकों मुसीबतें झेली हैं उनके लिए जमीन देने की आपने कोई व्यवस्था की है, ताकि परती जमीन को वह उपजाऊ बना कर उत्पादन बढ़ा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यहां हम मुर्गियों के लिए दाना देने की बात कर रहे थे अब आप पोलिटिकल सफरसं के ऊपर चले गये ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस स्टेटमेंट के दूसरे भाग को देखने से मालूम होता है कि 93500 डालर की सहायता आस्ट्रेलियन फ्रीडम फ्रौम हंगर कैम्पैन कमेटी ने 15 केन्द्रों को दी है और उससे मशीनें दी जायेंगी तो मैं जानना चाहता हूं कि वह 15 केन्द्र कौन कौन से हैं और किस प्रकार की मशीनें दी जायेंगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह तो हर एक जैसा कि मैंने अर्ज किया, बाबूगढ़ यह जो यहां से करीबन 30 मील दूरी पर है इस तरह का एक केन्द्र खोला गया है और इरादा है कि हर एक स्टेट में एक, एक केन्द्र खोला जाय । एक फीड मिक्सिंग प्लांट इक्विपमेंट है जिसमें कि मुर्गियों की खुराक के मुरक्कब तत्वों को मिला कर सस्ते दामों पर किसानों को दी जाती है ।